

रजिस्टर्ड न ० ल०-३३/एस० एम० १४.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 14 फरवरी, 1990/25 मार्च, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

रिपोर्ट-171002, 30 दिसम्बर, 1989

संघया आई०पी०एच०(३)/१४/८४.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम 8) की धारा II के अनुबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम सहृदय बनाते हैं:—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:—(i) ये नियम "हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियम, 1989" कहलायेंगे।
(ii) ये समस्त हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे।
(iii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक विषय और सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों;

- (i) “अधिनियम” से अभिप्राय : हिमाचल प्रदेश जलालूपति अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम 8) से है,
- (ii) “प्राधिकृत अधिकारी” से अभिप्राय: सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियन्ता/अधिकारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से है, जो उस कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित है,
- (iii) “फार्म” से अभिप्राय: उस फार्म से है जो इन अधिनियमों के साथ संलग्न है।
- (iv) यहां प्रयुक्त अन्य शब्दावलियों तथा पदों के जो प्रयोग किये गये हैं, परन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं उनके बहों अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में तदानुरूप दिए गये हैं।

3. पेयजल आपूर्ति स्कीमों को आरम्भ करने तथा उन्हें विनियमित करने की विधि (अधिनियम की धारा 3) नियम तथा शर्तें.—सरकार स्वयं अथवा स्थानीय लोगों के अनुरोध पर, क्षेत्र की आवश्यकताओं के निरीक्षण तथा अन्वेषण के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत नई स्कीम आरम्भ कर सकती है अथवा विद्यमान स्कीमों में सुगम ला सकती है।

(क) स्वोत में आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है, तथा

(ख) लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को लिखित रूप में यह वचन देना होगा कि वे अपनी भूमि के नीचे तथा ऊपर बिना किसी हरजाना अथवा क्षतिपूर्ति की मांग के पाईप बिछाने तथा अण्डारण जलाशय/जलाशय बनाने की अनुमति देंगे।

4. घरेलू कनैक्शन.—(1) स्कीम के विद्यमान कनैक्शनों में सभी नये कनैक्शन अथवा परिवर्तन, प्राधिकृत अधिकारी के लिखित आदेशों के अनुसार ही उपलब्ध करवाये जायेंगे जोकि अधीक्षण अभियन्ता के पद के निम्न स्तर का नहीं हो तथा इसका निष्पादन उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा जो कि प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार आदेश देने का अधिकार होगा।

(2) आपूर्ति लाईन से प्रत्येक निजी कनैक्शन के लिए स्टाप काक सहित पृथक् सर्विस पाईप उपभोक्ता को अपने खर्च पर उपलब्ध करवानी होगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी किसी विशेष स्कीम में निजी कनैक्शन के लिए मोटरों की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

(4) निजी कनैक्शन की सर्विस लाईन में से किसी भी अन्य निजी कनैक्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) निजी कनैक्शन से सम्बन्धित सभी कार्य प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों के आधार पर तथा उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।

(6) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत व्यक्ति के सिवाये, कोई भी अन्य व्यक्ति जल कनैक्शन अथवा मुख्य पाईप लाईन, नलका, टेक, बाल्ब, पाईप फिटिंग को नहीं खोलेगा, न विनियोजित करेगा तथा न ही इसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करेगा अथवा किसी बन्द काक, बाल्ब को न तोड़ेगा न क्षति पहुंचायेगा और न ही खोलेगा और स्वेच्छा से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे किसी पाईप अथवा किसी स्कीम के अन्य संबंधित का जल दूषित, बरबाद अथवा दुरुपयोग हो।

(7) यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी पाईप लाईन से पानी टपकता है अथवा पानी दूषित, है अथवा इसका दुरुपयोग हो रहा है अथवा पानी कालतू रूप से बह रहा है अथवा कोई ऐसा कारण विद्यमान है जिसके कारण पानी की पूर्ति में कमी आ रही है तो ऐसी स्थिति में वह विधिवत् नोटिस द्वारा किसी भी निजी कनैक्शन को अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति के अनुरूप काट सकता है। जिसके विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती।

(8) कोई भी नया कनैक्शन और किसी विद्यमान कनैक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन प्राधिकृत अधिकारी जो कि अधीक्षण अभियन्ता के पद के निम्न स्तर का नहीं हो के लिखित आदेशों के बिना उपलब्ध नहीं कराया जायेगा ऐसे नये कनैक्शन/परिवर्तन केवल उन्हों व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत हो तथा ये ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(9) प्राधिकृत अधिकारी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मध्य किसी भी समय निम्नलिखित स्थिति में ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकता है जिन्हें जल कर्नैक्षण दिये गये हैं,—

- (क) किसी पाईप, स्टाप काक, पिस्टन, मीटर अथवा अन्य फिर्टिंग के निरीक्षण, हटाने, परीक्षण, मुरम्मत अथवा बदलने के लिए; और
- (ख) पानी की टपकत, दुरुपयोग, प्रदूषण आदि का पता लगाने के लिए।

(10) यदि उपभोक्ता के नियन्त्रणाधीन किसी कर्नैक्षण में उसकी लापरवाही अथवा किसी अन्य कारणों से जिसके द्वारा पानी के अपव्यय, दुरुपयोग अथवा दूषित होने की आशंका हो तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कर्नैक्षण को तब तक के लिए काट सकता है जब तक कि उने डीक नहीं किया जाता। इस पर व्यव, यदि कुछ हो, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि जल कर्नैक्षण सरकारी नहीं है उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा।

(11) कोई भी ऐसा उपभोक्ता जिसके परिसर अथवा सम्पत्ति में सप्लाई लाईन के माध्य कोई कर्नैक्षण स्थापित किया गया है, यदि दो दिन की अवधि के भीतर जानवूकर अथवा लापरवाही से किसी क्षति अथवा पाईप कर्नैक्षण अथवा संचारण में हो रही तथा दीखने वाली टपकत को रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को नहीं देता तो उसे दोषी ठहराया जायेगा तथा उसे अधिनियम के अनुवन्ध (10) के अनुसार दण्डिया जायेगा।

(12) निजी कर्नैक्षण के पाईपों, स्टाफ कोक्स, मीटरों तथा अन्य उपकरणों के स्वामित्व के होते हुए भी ये सभी प्राधिकृत अधिकारके नियन्त्राधीन समझे जायेंगे।

(13) प्राधिकृत अधिकारी शौचालय, निजी मुवालय तथा किसी विशेष स्कीम के शौचालयों के लिए जल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में निर्णय करेगा, तथा प्राविकृत अधिकारी के लिए यह भी विधि संगत होगा कि वह इस तरह के आकार तथा प्रकार के हीज आदि के प्रयोग को सुनिश्चित कर सकता है। जैसा कि वह उक्त शौचालयों, निजी मैत्रालयों व जल शौचालयों आदि के लिए निर्दिष्ट करें ऐसे सभी जल हीज उपभोक्ता के खर्च से उपलब्ध करवाएं तथा लगवाये जायेंगे।

(14) स्टीम उत्पादन के प्रत्येक बायलर के लिए जल जलाशय से उपलब्ध करवाया जायेगा न कि सीधी सर्विस लाईन से ऐसे प्रत्येक जलाशय के लिए मीटर बाल बाल्व, संचूक अथवा उसके निरीक्षण हेतु उचित सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। उपरोक्त व्यवस्था का खर्च उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(15) जो उपभोक्ता निजी कर्नैक्षण लगाना चाहता है वह फार्म “क” पर आवेदन करेगा जो कि प्राधिकृत अधिकारी से 2 रु की अदायगी से प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार का कर्नैक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो कि अधीक्षण अभियन्ता के पद के निम्न स्तर का नहीं हो प्रणाली में जल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर स्वीकृत करेगा कि अन्य सार्वजनिक नल तथा निजी कर्नैक्षणों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस विषय में फार्म “ख” में सूचना दी जायेगी।

5. वाणिज्य कर्नैक्षण.—(1) जो उपभोक्ता व्यापारिक कर्नैक्षण लगाना चाहता हो वह फार्म “क” में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि प्राधिकृत अधिकारी से दो रु 0 की अदायगी से प्राप्त होगा। इस प्रकार का कर्नैक्षण प्राधिकृत अधिकारी से जो कि अधीक्षण अभियन्ता के पद के निम्न स्तर का नहीं हो द्वारा प्रणाली में जल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर स्वीकृत करेगा कि अन्य सार्वजनिक नल तथा निजी कर्नैक्षणों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कर्नैक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अगल मीटर देविया जायेगा तथा स्वीकृत फार्म “ख” में सूचित की जायेगी।

(2) यदि घरेलू जल आपूर्ति में कमों हो तो प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस देकर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए दी गई, जल सप्लाई को अलग करने का अधिकार होगा।

6. घरेलू/व्यापारिक कर्नैक्षणों के लिए प्रतिभूति.—शहरी क्षेत्रों में नये कर्नैक्षणों के लिए उपभोक्ता 50 रु 0 की प्रतिभूति घरेलू कर्नैक्षणों के लिए तथा 100 रुपये की प्रतिभूति व्यापारिक कर्नैक्षणों के लिए जमा करवायेगा तथा 25 रुपये की प्रतिभूति घरेलू कर्नैक्षणों तथा 100 रुपये की प्रतिभूति व्यापारिक कर्नैक्षणों के लिए जमा करवायेगा।

7. मीटर लगाने का प्रावधान.—(1) शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी कनैक्शनों में मीटर लगाये जा सकते हैं।

(2) ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए पानी के निजी कनैक्शन सरकार द्वारा समझौते पर निर्धारित समान दरों पर प्रदत्त किये जायेंगे तथा इन योजनाओं में मीटर लगाए जाने की अनुमति नहीं है।

(3) यदि सरकार द्वारा पानी के कनैक्शन के साथ मीटर प्रदान किया गया है तो उपभोक्ता द्वारा 2 रु प्रतिमास की दर से मीटर का भाड़ा देना होगा। यह भाड़ा पानी के प्रभार के अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त मीटर की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पच्चास रुपये होगी।

(4) मीटर चाहे सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो अथवा उपभोक्ता द्वारा स्वयं लिया गया हो, प्राधिकृत अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेगा। मीटर लगाने, नालियों को फिट करने तथा अन्य उपकरणों को लगाने का खर्च उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा। मीटर लगाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। मीटर लगाना हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित की गई राशि अग्रिम रूप में उपभोक्ता द्वारा जमा करवानी होगी।

(5) उपभोक्ता उसके परिसर में लगाए गए पानी के मीटरों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा। मीटर को किसी प्रकार की टूट-फूट, मुरम्मत अथवा बदले जाने का खर्च उपभोक्ता द्वारा देय होगा। उपभोक्ता इसके लिए जिम्मेवार होगा कि मीटर कोई क्षति अथवा छेड़खानी न हो। प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा उपभोक्ता द्वारा पालनीय होगा। यह खर्च उपभोक्ता से पानी के प्रभार के साथ लिया जायेगा और यदि वह निर्धारित समय में ऐसा करने में असकल होता है तो विना किसी अन्य नोटिस के पानी का कनैक्शन काट दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में बकायों का समंजन प्रतिभूति की राशि में से किया जायेगा, पूरा न होने की स्थिति में इस लगान के बकाया के रूप में बसूल किया जायेगा।

(6) मीटर के निरीक्षण, परीक्षण अथवा बदलने के लिए उपभोक्ता 20 रुपये की अग्रिम राशि सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। मीटर को 5 प्रतिशत तेज/धीर्घ में पाये जाने की स्थिति में निरीक्षण का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जायेगा और उपभोक्ता द्वारा जमा करवाई गई अग्रिम राशि आगे के बिलों में समर्पित की जायेगी। अथवा यह अग्रिम राशि लौटाई अथवा सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(7) मीटर में यदि कोई दोष पाया गया तो कम से कम 12 मास को पानी की आपूर्ति अथवा मीटर लगाते समय से, पहले की मीटर रीडिंग, जो भी कम हो बसूल की जाएगी।

8. जल प्रभार की बसूली को नियमित करने की पद्धति.—(1) शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक नलों, गलियों में नलों को अदि द्वारा जल आपूर्ति की अदायगी स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को करेगा तथा अपने स्तर पर व्यक्ति उपभोक्ता परिवार से बिल एकत्रित करेगा। विभाग द्वारा चलाई जा रही शहरी क्षेत्र की स्कीमों में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता जल प्रभार एकत्र करेगा तथा सीधे उपभोक्ताओं को बिल जारी करेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कनैक्शनों के प्रभार नम्बरदार द्वारा एकत्र किये जायेंगे। एकत्रित किए गए प्रभारों में से 20 प्रतिशत बताऊं कमीशन काट कर बाकी राशि सम्बन्धित कोषालय में नम्बरदार द्वारा निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाएगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति.—0215—जल आपूर्ति एवं सैनीटेशन, 01—जल आपूर्ति, 102—ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ।

नम्बरदार के द्वारा एकत्रित की गई राशि को 15 दिन के अन्दर कोषालय में जमा करना होगा अन्यथा, वह कमीशन का हिस्सेदार नहीं होगा।

शहरी जल आपूर्ति.—शहरी क्षेत्रों में निजी कनैक्शनों के लिए प्रयोज्य प्रभारों की अदायगी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को करनी पड़ेगी तथा निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाएगी।

0215—जल आपूर्ति सैनीटेशन, 01—जल आपूर्ति, 103—शहरी जल आपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ।

(3) जल उपभोग, मीटर भाड़ा तथा अन्य प्रभार यदि कोई हो, के बिल यथा सम्भव नियमित रूप से

प्रस्तुत किये जायेंगे। जो ऋमिक विलों का अन्नराज शहरी आपूर्ति योजना की स्थिति में एक से तीन मास तथा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की स्थिति में दो से छः मास का होता। उपर्योक्ता द्वारा उसकी अदायगी विल जारी होने की तिथि रो 15 दिनों के भीतर की जाएगी। यदि अदायगी निर्वाचित भवन में नहीं की जाती तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिकार लगाया जाएगा। यदि अतिरिक्त अधिकार सहित अदायगी अगले 15 दिनों तक नहीं की जाती जो प्राधिकृत अधिकारी कर्नेक्षन काट लेगा। यदि प्रतिशत नहीं है अथवा प्रतिशत की राशि कम से कम है तो इस स्थिति में अदायगी की भूमि के नगाने के बकाए के रूप में वसूल किया जाएगा देवारा कर्नेक्षन लगानाने के लिए 20/- रुपये का शुल्क होता तथा साद कागज पर प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करन का विचार किया जा सकता है।

(4) प्राधिकृत अधिकारी निसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि अधिनियम अथवा नियम में उपर्युक्त नियमों को भंग करता है के विरुद्ध राज्य सरकार के निर्देशनभार विषय के सज्ञान के अनुसार उसी के व्याधार्वीण के सम्मुख सुकृदमा दायर करेगा, जो इसके लिए सदम है।

आदेशानुभार,

प्र०, क० महोपाधी,
आयुक्त एवं सचिव ।

प्ररूप "क"

[(नियम 4 (15) देखें)]

नये घरेलू/व्यापारिक जल कर्नेक्षन/जल कर्नेक्षन के विस्तार के लिए आवेदन

[जो शब्द अप्रोज्य हो उन्हें काट दें]

सेवा में,

अधिकारी अभिभूता,

-
 1. मकान का नाम
 2. मुहल्ला
 3. निर्माण का वर्ष
 4. भवन के स्वामी का नाम
 5. कर्नेक्षन लेने वाले व्यक्ति का नाम, चाहे वह स्वामी हो अथवा किरायेदार
 6. क्या कर्नेक्षन नये भवन निर्माण हेतु, अथवा पुराने भवन के लिए वांछित है
 7. नव निर्मित भवन की स्थिति में क्या इसके पूरा किए जाने का नक्शा मकान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है
 8. संचारण नंबर का परिमाण
 9. वांछित पक्षालन टंकियो (यदि कोई हो) की संख्या, अन्य अपेक्षित फिटिंग के विवरण सहित

10. विद्यमान फिटिंग का विवरण
 11. स्वामी/किरायेदार का नाम तथा हस्ताक्षर
 12. स्वामी/किरायेदार का पताचार के लिए पता

कार्यकारी अभियन्ता ।

आवेदक,
स्वीकृति प्रदान करने वाले,
प्राधिकारी के हस्ताक्षर ।

पाद टिप्पणी.—इस आवेदन पत्र के साथ स्थल नक्शा साथ लगाना होगा जिसमें निकटतम जल मेन तथा वे बिन्दु जहां से कनकशन लिया जाना आपक्षित है दर्शाया जाना चाहिए।

प्रहृष्ट “ख”

[नियम 4 (15) देखें]

हिमाचल प्रदेश सरकार
सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

संख्या:

दिनांक:

सेवा में

विषय: मकान कनेक्शन ।

आपके आवेदन संख्या दिनांक
के संदर्भ में आपके मकान/परिसर के लिए फ्लैट दर/मीटर के अनुसार जन दरक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के प्रधायाधीन व्यास का घरलू कनकशन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :—

1. पूर्ण लाईन से आप के मकान/परिसर तक पाईप लाईन तथा अन्य आवश्यक उपकरण आप द्वारा अपने खर्च पर लगाय जायेंगे ।
2. पाईप लाईन के साथ वहिल वाल्व तथा नक्शे के अनुसार चिनाई द्वारा निर्मित प्रकोष्ठ में जल मीटर विसमें ताले का उचित प्रबन्ध हो आपको अपने खर्च पर उपलब्ध करवाने होंगे ।
3. कनेक्शन के लिए जल मीटर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा यह आपको स्वयं उपलब्ध करवाना होगा । सरकार द्वारा मीटर दिये जाने की स्थिति में आपको जल प्रभार के अतिरिक्त 2 रुपये प्रति मास की दर से किराया देना होगा । आपको मीटर प्रकोष्ठ तथा जल नल के मध्य रेखा चिह्न के अनुसार 30 से 0 मी \times 030 से 0 मी 0 आकार का एक अन्य निर्मित प्रकोष्ठ भी अपने खर्च पर बनवाया होगा ताकि एक अन्य वहिल वाल्व की व्यवस्था की जा सके । जिसके द्वारा आप जल रिसाव अथवा जल के उपभोग पर नियन्त्रण कर सकें । प्रकोष्ठ के ताल की चाबी आपके पास रहेगी ।

4. आपूर्ति लाईन से आपके मकान/परिसर तक पाईप विछाने के मन्दन्ध में आपको भू-स्वामीं की अनुमति प्राप्त करनी होगी यदि ऐसी लाईन किसी निर्जी भूमि से गुजर रही हो।
5. कनेक्शन आपको अपने जाविम पर दिया जायेगा तथा विभाग स्कीम के अवधीन नानी की कमी होने की अवस्था में आपके मकान/परिसर में जल आपूर्ति हेतु उत्तराधी नहीं होगा।
6. यदि ऐसा पाया जाए कि आपके जल कनेक्शन की स्कीम को जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो विभाग की स्वीकृति वापिस लेने का अधिकार होया।
7. आप इस बात के लिए जिम्मेवार होंगे कि मीटर आपकी सुरक्षित अभिरक्षा में है तथा इस पर नगी मोहर में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं की गई है।
8. आपको 50 रु 50 अथवा 100 रुपये की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होगी।
9. आपको, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसंचित जल दरों के अनुनार विल दिये जाने की तिथि में 15 दिन के भीतर नियमित रूप से अदायगी करनी होगी, इस अवधि के पश्चात 10 प्रतिशत अविभार दिया जायेगा। अगले 15 दिन के अन्दर भुगतान न करने अथवा विलम्ब की अवस्था में विभाग को आपके मकान/परिसर के जल कनेक्शन काटने की छूट होगी तथा विल या समायोजन जलापूर्ति अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियमों के अनुपरुक्त किया जायेगा।
10. यदि आप उपरोक्त शर्तों तथा नियमों से सहमत हैं तो आप से अनुरोध है कि आप सहायक अभियन्ता सिचाई एवं जल स्वास्थ्य उप-मण्डल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सम्पर्क स्थापित करें तथा कनेक्शन प्राप्त करने के मन्दन्ध में आवश्यक रुप जमा करवायें।
11. तथापि कोई भी कार्यवाही केवल उसी स्थिति में की जायेगी जब उपरोक्त शर्तों एवं नियमों को नुरा किया गया हो तथा इस विभाग के प्रांतिकृत प्रतिनिधि के निरोक्षण पर सभी प्रबन्ध सन्तोषजनक पाये गय हैं।

[Authoritative English text of draft notification No. IHP(3)14/84, dated 30-12-1989, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 1989

No. IPH(3)14/84.—In exercise of the powers conferred by section-II of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(i) These rules shall be called the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989.
 (ii) It extends to the whole State of Himachal Pradesh.
 (iii) These shall come into force at once.
2. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:—
 (i) “Act” means the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act 8 of 1969);
 (ii) “Authorised Officer” means, Superintending Engineer/Executive Engineer/Assistant Engineer of Irrigation and Public Health Department of the State of Himachal Pradesh for the area within his jurisdiction,
 (iii) “Form” means the form as appended to these rules;
 (iv) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Manner to regulate and initiate Drinking water supply schemes (section 3 of the Act),**

Principles and conditions.—The Government may initiate new schemes or improve upon the existing schemes after investigating surveying the requirements of the areas, on its own or on a request from the local inhabitants, subject to the following conditions:—

(a) sufficient water is available to be tapped at the source; and

(b) the inhabitants to be benefited are to give an undertaking in writing to allow the laying of pipes and construction of storage tank/tanks under and over their land without any compensation.

4. House connections.—(1) All new connections or alterations to the existing connections in a scheme shall be provided with the written orders of the authorised officer not below the rank of Superintending Engineer and its execution may be done through his representative which will be open for inspection to the authorised officer, who shall be competent to issue further directions, if need so.

(2) Separate service pipe line may be provided from the main supply line with a stop-cock at the cost of the consumer for each private connection.

(3) The authorised officer not below the rank of Superintending Engineer may allow the installation of meters for private connection in a particular scheme.

(4) No other private connection shall be allowed from the service pipeline of the private connection.

(5) All works, relating to the private connection shall be executed to the entire satisfaction of the authorised officer as per his directions.

(6) No person other than a person duly permitted by the authorised officer shall open, disconnect, interfere with the water connection or mains, hydra it, tank, valve, fittings or break, injure, open any locked cock, valve, pipe and wilfully do any action whereby the water in any pipe or other component of the scheme is contaminated or wasted or mis-used.

(7) The authorised officer not below the rank of Superintending Engineer with due notice, may disconnect any private connection, if he is satisfied that there is leakage in the pipe line or water is contaminated or wasted or mis-used or there is sufficient cause to deficiency in water supply, which would not be questioned in any court of law.

(8) No new connection on the alteration to the existing connection shall be allowed without the written orders of the authorised officer not below the rank of Superintending Engineer. Such new connections alterations shall be made by such person(s) as may be permitted by the authorised officer and these shall remain open for inspection to the authorised officer; who shall be competent to issue further directions if needed so.

(9) The authorised officer may at any time between sunrise and sunset enter upon any premises to which a private water connection has been provided for,—

(a) testing, removing, examining, repairing or replacing any pipe, stop-cock, cistern, meter or other fittings; and

(b) detecting wastage, misuse, contamination etc., of the water.

(10) If any defect is noticed in the private connection under the control of the consumer due to his negligence or any other circumstances which is likely to cause wastage, mis-use or contamination of water, the authorised officer may get it disconnected until the defects are rectified and charges therefore, if any, paid by the private consumer.

(11) If any private consumer in whose premises or property any private connection has been provided with the supply pipe line wilfully or negligently omits to report within two days to the authorised officer any damage or leakages happening or appearing in any pipe connection or communication shall deemed to have committed an offence under section 10 of the Act.

(12) Notwithstanding the ownership of pipes, stop-cocks, meter and other appurtenances of private connection, the connection as a whole shall be under the control of the authorised officer.

(13) The authorised officer shall decide in relation to providing of water for latrines, privices urinals and water closet in particular scheme and it shall also be lawful for the authorised officer to require use of cisterns of such sizes and description as he may direct to the said latrines,

privices urinal and water closet etc. all such cisterns shall be provided and fixed at the cost of consumer.

(14) Every boiler for generating steam shall be supplied with water from a reservoir and not direct from the service line. Every such reservoir shall be provided with a meter, a ball valve, a detective or proper means of access for inspection thereof. The cost of aforesaid installations shall be borne by the consumer.

(15) A person who intends to get a private connection, shall submit an application in Form 'A', obtainable from the authorised officer on the payment of Rs. 2/- . The connection may be sanctioned by the authorised officer not below the rank of Superintending Engineer on the availability of water in the system subject to the conditions that other public hydrants, private connections are not adversely affected. The sanction shall be conveyed in Form 'B'.

5. Commercial connection.—(i) A person, who intends to get commercial connection shall submit an application in Form 'A' obtainable from the authorised officer on payment of Rs. 2/- . The connection may be sanctioned by the authorised officer not below the rank of Superintending Engineer on the availability of water on the system subject to the condition that other public hydrants, private connections are not adversely affected. The connection shall be allowed through a separate meter by the authorised officer and the sanction shall be conveyed in this behalf in Form 'B'.

(ii) The authorised officer, with due notice, shall have the power to disconnect the supply for commercial purposes if the domestic supply is found to be deficient.

6. Security for house/commercial connections.—A consumer for new connections in urban areas shall deposit security of Rs. 50/- for domestic and Rs. 100/- for commercial connection and in rural areas, security shall be Rs. 25/- for domestic and Rs. 100/- for commercial connections.

7. Providing of Meter.—(i) For urban water supply schemes, private connections may be given by the authorised officer not below the rank of Superintending Engineer after installation of meters.

(ii) For rural water supply schemes, a private water connection shall be allowed on out such flat rates as may be fixed by the Government from time to time and the installation of meters is not permissible.

(iii) If the meter is provided by the Government with the water connection, the rent of meter at the rate of Rs. 2/- per month shall be payable by the consumer. This rent shall be in addition to the water charges. Additional security of meters shall be Rs. 50/- which shall be refundable.

(iv) The meters whether provided by the Government or arranged by the consumers shall be under the control of the authorised officer, and the cost of installation of meter, fixing of pipes, appurtenances etc. shall be paid by the consumer. The consumer shall deposit the cost intimated by the authorised officer in advance for installation of the meter.

(v) The consumer shall be fully responsible for the safe custody of water meter provided to his premises. The cost of any damage, repair, replacement of the meter shall be payable by the consumer who will be responsible to ensure that no damage or tampering to the meter is done. The decision of the authorised officer shall be final and binding on the consumer. Such cost may be recovered from the consumer along with the water charges and in case he fails to pay the same within the period specified, the connection may be disconnected without any further notice. Arrears on this account will be adjusted from the security failing which the same shall be recovered as arrears of land revenue.

(vi) The consumer shall submit an application accompanied by a fee of Rs. 20/- for the purpose of testing or examining or repairing or replacing a meter. In case the meter is proved to be fast/slow by 5% or more, the cost of the testing will be borne by the Government and the advance money deposited by the consumer shall be adjusted in the future bills, otherwise this advance shall not be refunded or adjusted.

(vii) If any defect is noticed in the working of the meter, average of at least 12 months of the water tax or the previous reading at the time of installation of meter whichever is less will be recovered.

8. Manner to regulate the recovery of water charges. —(i) In the urban areas, the local authority shall make the payment of supply of water made through public hydrants, street taps, etc. to the Assistant Engineer concerned and collect the bills from the individual consumer family at their own level. In urban areas schemes which are being maintained by the Government the concerned Assistant Engineer shall collect the water charges and also issue the bills to the consumers directly.

(ii) In rural areas for private connections, the charges shall be collected by the Lombardars. Out of the collection charges made, 20% towards commission shall be deducted by the Lombardars and the balance amount shall be deposited in the Treasury in the following head of account:—

RURAL WATER SUPPLY

0215—Water Supply and Sanitation, 01—Water Supply, Receipts for Rural WSS.

The Lombardars will deposit the amount so collected in the Treasury within 15 days of collection failing which they will not be entitled for commission.

URBAN WATER SUPPLY

In the urban areas for private connections the charges as applicable shall be paid to the Assistant Engineer concerned and shall be debited to the following Head of Account.—

0215—Water Supply, Sanitation, 01—Water Supply, 103—Receipts for Urban W.S.S.

(iii) The bills for consumption of water, rent of meter and other charges if any, shall be presented as regularly as possible. The interval between two successive bills being one month, to three months in case of urban water supply scheme and 2 to 6 months in case rural water supply schemes. The payment thereof shall be made by the consumer within 15 days of the date of issue of the bills. If the payment is not made within the stipulated period, a surcharge of 10% shall be imposed extra. If the payment is not made for another 15 days along with the surcharge the authorised officer may disconnect and adjust the bill out of security deposit. In case no security deposit is lying or the amount of security is less, the same shall be recovered as arrears of land revenue. Fee for reconnection shall be Rs. 20/- and can be considered on submission of application on plain paper to the authorised officer.

(iv) The authorised officer shall file a complaint against the person whosoever commits a breach of any provision of the Act or rules before a such Magistrate to take the cognizance of the case as the Government may direct in this behalf.

By order,
Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

FORM 'A'
[See Rule 4(15)]

APPLICATION TO TAKE NEW DOMESTIC/COMMERCIAL WATER CONNECTION/ EXTENSION OF WATER CONNECTION

(Cross out any of the words which are not applicable)

To

The Executive Engineer,

1. Name of house

2. Locality
3. Year of construction
4. Name of owner of the building
5. Name of person desiring to have the connection, whether owner or tenant
6. Is the connection sought for a new or old construction
7. In case of new construction, has the completion plan been approved from the competent authority
8. Size of communication pipe
9. Number of flushing cisterns required (if any) with description and other fittings required
10. Detail of existing fitting
11. Name and signatures of the owner/tenant
12. Address of the owner/tenant for correspondence

Applicant,

Signature of the sanctioning authority.

Executive Engineer.

*Foot note.—*This application should be accompanied by a site plan showing nearest water mains and points where connections are desired.

FORM "B"

[See rule 4 (15)]

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

No.....

Date.....

To

.....
.....

*Subject.—*House connection.

Ref: Your application No....., dated
sanctioned to your house/premises on flat rate/metered water rate basis subject to the under noted conditions:-

1. The pipe lines and other necessary appurtenances to your house/premises shall be laid by you at your cost from the supply line.
2. The pipe line shall be provided with wheel valve and water meter provided in a masonry chamber as per drawing having proper locking arrangements at your cost.
3. Water meter may be provided by the Government for connection or you may be required to provide the same. In case it is provided by the Government, you shall be liable to pay Rs. 2/- per month towards the rental charges besides water charges. You shall also construct another masonry chamber of 30 cm × 30 cm size as per drawing between the chamber for meter and water tap to provide another wheel

- valve at your cost whereby the consumption or the leakage of water could be controlled by you. The key of the lock of this chamber shall remain in your custody.
4. You shall arrange permission of the landowner to allow the laying of the pipeline from the supply line to your house/premises through private land if any.
 5. The connection shall be provided to you at your risk and the Government does not accept the liability of supply of water to your house/premises on account of scarcity of water in the scheme.
 6. The Government reserves the right to withdraw the sanction in case it is found that your connection adversely affects the supply of water in the scheme.
 7. You shall be responsible to encure that the meter is in your safe custody and the seal is not tampered with.
 8. You shall deposit Rs. 50/- or Rs. 100/- towards security.
 9. The water rate as notified by the Government from time to time shall be payable by you regularly wthin 15 days of the presentation of the bill whereafter the surcharges of 10% shall be leviable. In case of default of payment or delay by the next 15 days, the authorised officer shall be at liberty to disconnect your house/premises connection and adjust the bill as per rules notified under the Act.
 10. If you agree to the above terms and conditons, you are requested to contact the Assistant Engineer, I.P.H. Sub-Division, H.P.P.W.D..... and deposit necessary amount for getting the connection.
 11. The action shall, however, be taken only after the above terms and conditions have been fulfilled and all the arrangements have been found to be satisfactory on inspection by the authorised representative of this Department.